PLUTUS IAS

UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

08/07/2024 से 14/07/2024 तक

THE HINDU

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. स्मार्ट सिटीज मिशन का मार्च 2025 तक विस्तार..... 1
2. भारत के स्वदेशी लाइट टैंक ज़ोरावर का अनावरण..... 3
3. विश्व ज़ूनोसिस दिवस 2024 5
4. सेहर (SEHER) कार्यक्रम / योजना..... 7
5. विश्व जनसंख्या दिवस 2024 और भारत में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे 9
6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नया वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित..... 11

करंट अफेयर्स
जुलाई 2024

स्मार्ट सिटीज मिशन का मार्च 2025 तक विस्तार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था , स्मार्ट सिटी मिशन : महत्त्व और चुनौतियाँ , शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' स्मार्ट सिटी मिशन, सतत् विकास, विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT)' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' स्मार्ट सिटी मिशन का मार्च 2025 तक विस्तार ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की समयसीमा को फिर से बढ़ा दिया है।
- अब इस मिशन को 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह मिशन भारत के शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य शहरों को तकनीकी और डिजिटल समाधानों के माध्यम से सुधारना है।
- इस मिशन के तहत, 100 शहरों ने विभिन्न परियोजनाओं का विकास किया है। इन परियोजनाओं के तहत शहरों की क्षमता और अनुभव में सुधार हुआ है और शहर के स्तर पर बड़े परिवर्तनकारी लक्ष्य हासिल हुए हैं।

स्मार्ट सिटी क्या है ?

- स्मार्ट सिटी एक अवधारणा है जो शहरी क्षेत्रों में दक्षता, स्थिरता के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा एवं नवीन समाधानों के उपयोग को संदर्भित करती है।
- इसके मुख्य बुनियादी ढाँचे में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता, सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, सुशासन, ई-गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी, पर्यावरण की धारणीयता, और नागरिकों की सुरक्षा शामिल हैं।
- वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग %31 हिस्सा शहरों में निवास करती है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इनका योगदान %63 है।
- यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक भारत की %40 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान %75 होगा।

स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) :

- स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) भारत सरकार द्वारा देश भर के शहरों और कस्बों में निवास करने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया एक योजना है।
- इसे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ और स्थायी वातावरण प्रदान करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है।

SCM के मुख्य घटक :

स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के मुख्य घटक निम्नलिखित है –

क्षेत्र-आधारित विकास :

पुनर्विकास (शहर नवीनीकरण) : मौजूदा शहरी क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए नवीनीकरण करना।

रेट्रोफिटिंग (शहर सुधार) : मौजूदा क्षेत्रों को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।

ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ (शहर विस्तार) : स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ नए शहरी क्षेत्रों का विकास करना।

पैन – सिटी समाधान :

- ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधानों का अनुप्रयोग किया जाता है।

शासन संरचना :

- नवीन शासन मॉडल को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) बनाया गया, जिसका नेतृत्व नौकरशाह या बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC) के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नवीन शासन मॉडल अपनाया गया।

स्मार्ट शहरों का वित्तपोषण :

- SCM के लिए केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए प्रदान किए गए लगभग 48,000 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपये) इन शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को भी समान राशि का योगदान करना आवश्यक है, जिससे कुल मिलाकर यह राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपये हो जाती है।

अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण से प्राप्त होने वाला लाभ :

- SCM के संसाधनों और उद्देश्यों को AMRUT (शहरी रूपांतरण), स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छता), HRIDAY (विरासत शहर विकास), डिजिटल इंडिया, कौशल विकास, और सभी के लिए आवास जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ती है।
- SCM के तहत समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में विभिन्न योजनाओं के मौजूदा फंड एवं बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जा सकता है।
- अन्य योजनाओं के साथ इसके अभिसरण से यह सुनिश्चित होता है कि स्मार्ट शहरों में भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे (स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति) को भी प्रमुखता दी जाए।
- SCM को इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत किया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन के समक्ष चुनौतियाँ :

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के सफल क्रियान्वयन के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं –

- **परियोजना की पूर्णता में विलम्ब** : इस योजना के तहत अभी तक लगभग %10 परियोजनाएँ अधूरी हैं, जो कि इस परियोजना के निष्पादन में देरी का संकेत है। इसके पीछे तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, भूमि अधिग्रहण की समस्या और अन्य समस्याएँ हो सकती है।
- **वित्तपोषण की कमी :** भारत के 26 शहरों को अभी भी पूर्ण वित्तीय राशी नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि 74 शहरों को उनके केंद्रीय हिस्से का %100वित्तीय राशि प्राप्त हो गया है।
- **SPV मॉडल की चुनौतियाँ :** स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए अपनाए गए Special Purpose Vehicle (SPV) मॉडल को संविधान संशोधन के साथ गलत संरेखण के कारण आपत्तियों का सामना करना पड़ा है।
- **समन्वय की कमी :** इस योजना के तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय की आपसी कमी के कारण मिशन के निर्बाध कार्यान्वयन में बाधाएँ आई हैं।
- **विस्थापन और सामाजिक प्रभाव :** इस योजना से गरीब क्षेत्रों के निवासियों का विस्थापन हुआ है, जिससे शहरी समुदायों का ताना-बाना बाधित हुआ है। कुछ कस्बों में बुनियादी ढाँचे के विकास ने जल प्रणालियों में व्यवधान के कारण शहरी बाढ़ में वृद्धि में योगदान दिया है।

समाधान / आगे की राह :

स्मार्ट सिटी मिशन को प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जा सकता है –

प्रभावी शासन एवं योजना का कार्यान्वयन :

- निश्चित कार्यकाल वाले CEOs की नियुक्ति से निरंतरता सुनिश्चित होगी और योग्य पेशेवरों को आकर्षित किया जा सकेगा।
- विशेषज्ञों और संसद सदस्यों (MPs) सहित विभिन्न हितधारकों को समावेशी निर्णय लेने पर बल देना चाहिए।

परियोजना पर रणनीतिक फोकस :

- स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) डिजिटल बुनियादी ढांचे के तहत विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न और उपयोग करने की योजना है। इसलिए, इन प्लेटफार्मों को साइबर हमलों से बचाने के साथ-साथ संवेदनशील सार्वजनिक और निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करनी चाहिए।

डेटा सुरक्षा और उसका उन्नयन :

- साइबर खतरों का मुकाबला करने और डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना की जानी चाहिए।
- बुनियादी ढांचे की समयावधि को अधिकतम करने और समय पर इसका उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए संचालन और रखरखाव संबंधी समग्र रणनीति विकसित करनी चाहिए।

क्षमता निर्माण और वित्तपोषण :

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे शहरों में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को मजबूत बनाना चाहिए।
- इस क्रम में संगठनात्मक पुनर्गठन और कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार की सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है।

परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना :

- संबंधित मंत्रालय की भूमिका निधि आवंटन से विस्तारित होकर समय पर परियोजना निष्पादन हेतु सक्रिय निगरानी और विशेषज्ञता प्रदान करने तक होनी चाहिए।

वैश्विक ज्ञान साझाकरण :

- विकासशील देशों की सतत् शहरी विकास से संबंधित इसी तरह की परियोजनाएं इस संदर्भ में सूचना साझाकरण हेतु निर्णायक हो सकती हैं।
- भूटान की गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करते हुए दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा बनाना है। इसमें पर्यावरण मानकों और स्थिरता को प्राथमिकता देने से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से निवेश आकर्षित होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. स्मार्ट सिटीज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों को तकनीकी और डिजिटल माध्यम से सुधारना है।
2. वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इनका योगदान %63 है।
3. इसे जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था।
4. इस योजना के कारण शहरी बाढ़ में वृद्धि हुई है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के सफल क्रियान्वयन के समक्ष विद्यमान मुख्य चुनौतियाँ क्या है और उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है? (UPSC CSE – 2017 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत के स्वदेशी लाइट टैंक ज़ोरावर का अनावरण

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी, मेक इन इंडिया कार्यक्रम , रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' डीआरडीओ (DRDO) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T), डोगरा जनरल ज़ोरावर सिंह कहलूरिया , ज़ोरावर लाइट टैंक, रिमोट – कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम (RCWS) से लैस टैंक ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत के स्वदेशी लाइट टैंक ज़ोरावर का अनावरण ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारत ने हाल ही में डीआरडीओ (DRDO) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के संयुक्त सहयोग से निर्मित स्वदेशी लाइट टैंक **'ज़ोरावर'** का अनावरण किया है।
- यह टैंक उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका आदिप्रारूप (Prototype) अभी व्यापक परीक्षण के लिए तैयार है1।
- इस स्वदेशी लाइट टैंक 'ज़ोरावर' भारत-चीन सीमा (LAC) पर तैनात किया जाने की योजना बनाई गई है।

ज़ोरावर लाइट टैंक का परिचय :

- ज़ोरावर लाइट टैंक एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया हुआ हल्का टैंक है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और प्रमुख इंटीग्रेटर लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित

किया गया है।

- इस टैंक का नाम 19वीं शताब्दी के सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने जम्मू के राजा गुलाब सिंह के राज्य के अधीन कार्य किया था।
- ज़ोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल ज़ोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन-सिख युद्ध के समय कैलाश-मानसरोवर पर सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था।
- जनरल ज़ोरावर सिंह के सम्मान में नामित, इस टैंक को लद्दाख, सिक्किम, या कश्मीर में संभावित तैनाती से पहले व्यापक परीक्षणों के लिए तैयार किया गया है।
- यह टैंक रिकॉर्ड दो साल की समयसीमा के भीतर डिज़ाइन किया गया है और इसमें 105 मिमी राइफल वाली तोप और कम्पोजिट मॉड्यूलर कवच सहित उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियाँ हैं।

ज़ोरावर टैंक की विशेषताएँ :

ज़ोरावर टैंक, जिसे भारतीय सेना ने तैनात किया है, एक आधुनिक और हल्का टैंक है जो चीन के टाइप15- टैंकों के खिलाफ तैनात किया गया है। **इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –**

- **वजन :** ज़ोरावर टैंक का वजन अधिकतम 25 टन है, जो इसे हवाई मार्ग से भी ले जाने में सक्षम बनाता है।
- **ऊंचाई और तोपखाने की भूमिका :** यह टैंक उच्च ऊंचाई पर भी हमला करने में सक्षम है और सीमित तोपखाने की भूमिका निभा सकता है।
- **विभिन्न भूभागों में संचालन :** ज़ोरावर को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर द्वीपीय क्षेत्रों तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **आधुनिक तकनीकों से लैस :** यह टैंक आधुनिक तकनीकों से लैस है , जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, उच्च स्तर की स्थितिजन्य जागरूकता और जलस्थलीय संचालन क्षमता शामिल है।
- **टैंक के मूलभूत मापदंडों का संयोजन :** इसमें आग, शक्ति, गतिशीलता और सुरक्षा के मूलभूत मापदंडों का संयोजन किया गया है।
- **भारतीय सेना में इसे शामिल करने की योजना :** इसे भारतीय सेना में सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक शामिल किये जाने की संभावना है।
- **भारत के विभिन्न भू-भागों में कार्रवाई करने की विविधता प्रदान करने वाला टैंक :** ज़ोरावर एक भारतीय लाइट टैंक डिज़ाइन है। इसका उच्च शक्ति-भार अनुपात, भारी फायरपावर, सुरक्षा, निगरानी और संचार क्षमताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह भारतीय सेना को विविध खतरों और उसके प्रतिद्वंद्वियों की उपकरण प्रोफ़ाइल के खिलाफ विभिन्न भू-भागों में कार्रवाई करने की विविधता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **रिमोट – कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम (RCWS) से लैस टैंक :** यह टैंक रिमोट-कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम (RCWS) जैसी उन्नत प्रणालियों को एकीकृत करके बनाया गया है और इसे उभयचर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इस टैंक को विभिन्न इलाकों में सैन्य संचलन और सैन्य कारवाई की गतिशीलता को बढ़ाता है।

भारत के लिए ज़ोरावर टैंक का सामरिक महत्व :

- भारतीय सेना के लिए ज़ोरावर टैंक एक महत्वपूर्ण सामरिक उपकरण है।

- यह टैंक लद्दाख के गतिरोध के दौरान उजागर की गई सामरिक जरूरतों के जवाब में विकसित किया गया था।
- इसका वजन 25 टन है और यह पहली बार है कि एक नए टैंक को इतने कम समय में डिजाइन और परीक्षण के लिए तैयार किया गया है।
- 'ज़ोरावर' टैंक का डिज़ाइन सुनियोजन और परिचालन गतिशीलता में सुधार करता है।
- यह उच्च कोणों पर फायर करने, वायु द्वारा परिवहित करने और सीमित संख्या में तोपों का वहन करने में सक्षम है।
- इस टैंक का मुख्य उद्देश्य भारत के चुनौतीपूर्ण इलाकों में भारतीय सैन्य शक्ति की उपस्थिति को बढ़ाना और दुश्मन देशों के प्रहार को रोकना है।
- यह टैंक भारत की रक्षा क्षमताओं के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ज़ोरावर टैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसमें 105 मिमी राइफल वाली तोप और कम्पोजिट मॉड्यूलर कवच सहित उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।
2. ज़ोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल ज़ोरावर सिंह डोगरिया के नाम पर रखा गया है।
3. इस टैंक का अधिकतम वजन 45 टन है, जो इसे हवाई मार्ग से भी ले जाने में सक्षम बनाता है।
4. इसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के संयुक्त सहयोग से निर्मित किया गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 1 और 4

C. केवल 2, 3 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ज़ोरावर लाइट टैंक की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर द्वीपीय क्षेत्रों तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विश्व ज़ूनोसिस दिवस 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली , भारत का स्वास्थ्य एवं रक्षा प्रौद्योगिकी , वैज्ञानिक खोज और नवाचार ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग, लुई पाश्चर , जूनोटिक और गैर – जूनोटिक रोग ,सार्वजनिक स्वास्थ्य , स्वच्छता और पशुपालन प्रथाएँ , वन हेल्थ दृष्टिकोण , वेक्टर नियंत्रण ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' विश्व ज़ूनोसिस दिवस 2024 ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने विश्व ज़ूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया।
- इस सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय पशुपालन तथा डेयरी विभाग के सचिव (AHD) ने की।

विश्व जूनोसिस दिवस :

- विश्व जूनोसिस दिवस को हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोसिस रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- इस दिन को विशेष रूप से फ्रांसीसी जीवविज्ञानी लुई पाश्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने 1885 में रेबीज का पहला सफल टीका विकसित किया था।
- जूनोसिस रोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और परजीवी के कारण फैल सकते हैं, और इनमें रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा, निपाह, कोविड-19, ब्रुसेलोसिस और तपेदिक जैसे रोग शामिल हैं।

जूनोटिक और गैर-जूनोटिक रोग :

जूनोटिक रोग :

- ज़ूनोसिस संक्रामक रोग हैं जो जानवरों एवं मनुष्यों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसे रेबीज़, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह, कोविड19-, ब्रूसेलोसिस तथा तपेदिक।
- ये रोग विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं, जिनमें जीवाणु, विषाणु,

परजीवी, और कवक शामिल हैं। हालाँकि, सभी पशु रोग जूनोटिक नहीं होते हैं।

गैर-जूनोटिक रोग :

- कई बीमारियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा किए बिना पशुधन को प्रभावित करती हैं। ये गैर-जूनोटिक रोग प्रजाति-विशिष्ट हैं और मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। उदाहरणों में फुट एंड माउथ डिज़ीज, पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनैंट्स (PPR), लम्पी स्किन डिज़ीज, क्लासिकल स्वाइन फीवर, और रानीखेत रोग शामिल हैं
- सभी रोगों में से लगभग %60 ज़ूनोटिक हैं और %70 उभरते संक्रमण जानवरों से उत्पन्न होते हैं।
- भारत में वैश्विक पशुधन तथा मुर्गीपालन की संख्या क्रमशः %11 और %18 है। इसके अतिरिक्त, भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और अंडे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

जूनोटिक रोगों का प्रभाव :

जूनोटिक रोगों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकता है। जो निम्नलिखित है –

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य :** जूनोटिक रोगों के प्रसार के कारण रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। यह महामारी पैदा करने की क्षमता रखता है।
- **आर्थिक :** जूनोटिक रोगों से जुड़ी लागतें भी हो सकती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, पशु वध और व्यापार प्रतिबंधों से संबंधित।
- **सामाजिक :** जूनोटिक रोगों से जुड़ा भय और कलंक भी हो सकता है। इसके अलावा, आजीविका पर भी प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से कृषि और पशुपालन पर।

रोकथाम और नियंत्रण :

ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं –

- टीकाकरण :
  - गोजातीय बछड़ों के लिए ब्रुसेल्ला टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
  - रेबीज टीकाकरण के लिए भी राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत अभियान शुरू किया गया है।
- स्वच्छता और पशुपालन प्रथाएँ :
  - रोगों के प्रसार को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता और उचित पशुपालन प्रथाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- वेक्टर नियंत्रण :
  - इसके तहत रोग फैलाने वाले वेक्टरों को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं और रोग फैलाने वाले वेक्टरों को नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए।
- एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण / वन हेल्थ दृष्टिकोण :
  - इसके तहत मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
  - इसके तहत पशु चिकित्सकों, चिकित्सा पेशेवरों और पर्यावरण वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जूनोटिक रोगों का व्यापक रूप से समाधान किया जा सके।
- जनता को शिक्षित और जागरूक करना :
  - जूनोटिक और गैर-जूनोटिक रोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने से अनुचित भय को कम किया जा सकता है और पशु स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति अधिक सूचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - जूनोसिस रोगों के प्रति जागरूकता और उनके नियंत्रण के लिए सार्वजनिक जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम आवश्यक है।

इन उपायों के माध्यम से, जूनोटिक रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व ज़ूनोसिस दिवस के संबध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. जूनोसिस रोग जानवरों से मनुष्यों में फ़ैलाने वाला रोग है।
2. जूनोसिस रोग के नियंत्रण के सार्वजनिक जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रभावी टीकाकरण कार्यक्रम आवश्यक होता है।
3. सभी पशु रोग जूनोटिक रोग नहीं होते हैं।
4. जूनोटिक रोग से महामारी फैल सकता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.चर्चा कीजिए कि जूनोटिक बीमारियों से जुड़े जोखिमों को कम करने और सभी के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोगात्मक प्रयास और वन हेल्थ दृष्टिकोण क्यों आवश्यक हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

सेहर (SEHER) कार्यक्रम / योजना

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव / संग्रहण, विकास से संबंधित मुद्दे और रोज़गार , समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' नीति आयोग , महिला उद्यमिता मंच , ट्रांसयूनियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड, मानव संसाधन सशक्तीकरण सोसायटी कार्यक्रम ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' SEHER कार्यक्रम / योजना ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 8 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform – WEP) और ट्रांसयूनियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड [TransUnion CIBIL] ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मानव संसाधन सशक्तीकरण सोसायटी (Society for Empowering Human Resource – SEHER) कार्यक्रम / योजना को शुरू किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमियों के बीच वित्त, ऋण तक पहुँच और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसके लिए उन्हें आवश्यक संसाधन और उपकरण प्रदान करना है।
- महिला उद्यमिता मंच (WEP) मौजूदा हितधारकों के साथ अभिसरण और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से महिला उद्यमियों को निरंतर समर्थन मिलता है।
- SEHER कार्यक्रम को महिला उद्यमिता मंच (WEP) की मिशन निदेशक और नीति आयोग की प्रमुख आर्थिक सलाहकार, श्रीमती अन्ना रॉय द्वारा लॉन्च किया गया।

भारत में व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति :

भारत में महिलाओं के व्यवसाय में स्वामित्व की दृष्टि से वृद्धि हो रही है। यहां भारत में व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है –

MSME सेक्टर में महिलाओं का स्वामित्व :

- भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से लगभग %20 महिलाओं के स्वामित्व में हैं।
- ये उद्यम 27 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

व्यावसायिक ऋण की मांग :

- पिछले 5 वर्षों में (2019 से 2024) महिलाओं द्वारा व्यावसायिक ऋण की मांग में 3.9 गुना वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2019 और 2024 के बीच, महिला उधारकर्त्ताओं की हिस्सेदारी में %10 की वृद्धि हुई है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व :

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी शहरी क्षेत्रों (%18.42) की तुलना में अधिक है (%22.24)।
- यह वृद्धि महिलाओं के उद्यमिता में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

महिला उद्यमिता मंच (WEP) के बारे में प्रमुख तथ्य :

- महिला उद्यमिता मंच (WEP) को नीति आयोग द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया और 2022 में इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) में परिवर्तित कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन प्रदान करना और एक सक्षम वातावरण बनाना है।

उद्देश्य और कार्यक्षेत्र :

- **उद्यमिता संवर्धन :** महिला उद्यमिता मंच (WEP) महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद करता है।
- **वित्तीय संसाधनों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना :** वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करता है।
- **बाजार से संपर्क स्थापित करना :** महिला उद्यमियों को बाज़ार से जोड़ने में मदद करता है।
- **प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देना :** यह योजना महिलाओं को व्यावसायिक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देता है।
- **परामर्श और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करना :** परामर्श सेवाएं और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है।

- **व्यवसाय के विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करना :** व्यवसाय को विकसित करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।

सेहर (SEHER) योजना के प्रमुख लक्ष्य :

- **महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना :** महिलाओं को वित्तीय विषयों पर शिक्षित करना, जिसमें उनकी CIBIL रैंक और वाणिज्यिक क्रेडिट रिपोर्ट शामिल हैं।
- **व्यावसायिक कौशल प्रदान करना :** इस योजना के तहत महिलाओं को अपने व्यवसाय का प्रबंधन और विकास करने में सहायता के लिए संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
- **वित्त तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना :** इस योजना के तहत महिलाओं को यह समझने में सहायता करना कि वे प्रभावी रूप से ऋण तक कैसे पहुंच सकती हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकती हैं।
- **महिला उद्यमिता मंच (WEP) की भूमिका :** WEP (महिला उद्यमिता मंच) एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मंच है जिसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को समर्थन देने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- **ट्रांसयूनियन सिबिल की भूमिका :** यह वित्तीय जानकारी और क्रेडिट जानकारी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के वित्तीय कौशल में सुधार करना है।

सेहर कार्यक्रम / योजना का योगदान और प्रभाव :

- **MSME सेक्टर :** MSME मंत्रालय के अनुसार, भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जिनमें से %20.5 महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।
- **रोजगार सृजन करना :** इस योजना के तहत ये महिला-स्वामित्व वाले उद्यम 27 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- **ग्रामीण और शहरी उद्यमों का विभाजन :** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों का हिस्सा (%22.24) शहरी क्षेत्रों (%18.42) की तुलना में थोड़ा अधिक है।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान :** महिलाओं की उद्यमिता को तेज करके, भारत 30 मिलियन से अधिक नए महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों का निर्माण कर सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन और नौकरियों का सृजन हो सकता है।

आगे की राह :

- भारत में महिला उद्यमियों के लिए व्यवसाय ऋण की मांग वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक 3.9 गुना बढ़ गई है। मार्च 2024 में व्यवसाय ऋण वाले 1.5 करोड़ उधारकर्ताओं में से %38 महिलाएं थीं। इसी अवधि में महिलाओं द्वारा व्यवसाय ऋण के पोर्टफोलियो बैलेंस में %35 की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई है।
- महिला उद्यमिता मंच (WEP) और ट्रांसयूनियन CIBIL ने SEHER क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री और व्यावसायिक कौशल प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम उन्हें वित्तीय उपकरणों तक पहुंचने में मदद करेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में योगदान दे सकें।
- SEHER कार्यक्रम महिला उद्यमियों को अच्छा क्रेडिट इतिहास और CIBIL स्कोर बनाने के महत्व को समझाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों तक आसानी और तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी।
- महिला नेतृत्व वाले व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके स्थिर विकास के लिए त्वरित, सरल और किफायती वित्तीय पहुंच महत्वपूर्ण है। WEP और ट्रांसयूनियन CIBIL मिलकर देशभर में महिला उद्यमियों के बीच वित्तीय और क्रेडिट जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं।
- भारत में यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और बीमा फर्मों को सेवाएं प्रदान करती है।

स्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मानव संसाधन सशक्तीकरण सोसायटी कार्यक्रम (SEHER) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच और ट्रांसयूनियन सिबिल की एक संयुक्त पहल है।
2. यह एक व्यापक ऋण शिक्षा कार्यक्रम है जिसे महिला उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. न तो 1 और न ही 2

D. 1 और 2 दोनों

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सेहर (SEHER) कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह भारत में किस प्रकार महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अपना योगदान और प्रभाव उत्पन्न कर रहा है तथा उन प्रभावों से उत्पन्न समस्याओं का प्रभावी समाधान क्या है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विश्व जनसंख्या दिवस 2024 और भारत में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत 'भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान, महत्वपूर्ण प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग , महिलाओं से संबंधित मुद्दे, महिलाओं की भूमिका ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत की जनसंख्या , विश्व जनसंख्या दिवस 2024, राष्ट्रीय महिला आयोग , महिलाओं का प्रजनन – दर , भारत में जन्म और मृत्यु दर में मुख्य अंतर ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' विश्व जनसंख्या दिवस 2024 और भारत में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे ' खंड से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था	परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी	11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हुई, बढ़ती जनसंख्या बड़ी चिंता का विषय

- हाल ही में 11 जुलाई 2024 को वैश्विक जनसंख्या मुद्दों और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया।
- प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने के लिए इस दिवस की स्थापना वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी।

विश्व जनसंख्या दिवस का प्रारंभिक इतिहास और विकास – क्रम :

विश्व जनसंख्या दिवस का प्रारंभिक इतिहास और विकास – क्रम इस प्रकार है –

शुरुआत और विकास :

- 11 जुलाई, 1987 को, दुनिया की जनसंख्या करीब 5 अरब दर्ज की गई थी।
- इस घटना ने विश्व बैंक के एक वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ डॉ. के.सी. जकारिया का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस दिन को प्रत्येक वर्ष मनाने का सुझाव दिया।
- संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या से संबंधित चुनौतियों को पहचानते हुए डॉ. के.सी. जकारिया के इस सुझाव को अपनाया और वर्ष 1989 में आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए इसकी स्थापना की।
- अतः वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के विषय पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विश्व जनसंख्या दिवस का महत्व :

- इस दिन का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व आदि विषयों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है।
- विश्व जनसंख्या दिवस वैश्विक स्तर पर बढ़ती आबादी और उससे उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है और उन पर समाधान खोजने की प्रेरणा देता है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय (THEME) :

- विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय है – **" किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें (Leave no one behind, count everyone) "**
- विश्व जनसंख्या दिवस दुनिया के हर देश की सरकारों, संगठनों और जनसंख्या से संबंधित सभी लोगों के लिए यह दिशा प्रदान करता है कि कैसे उन्हें जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर काम करना चाहिए और उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए।
- यह दिन वैश्विक स्तर पर बढ़ती आबादी और उससे उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है और उन पर समाधान खोजने की प्रेरणा देता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व जनसंख्या दिवस 2024 के विषय / थीम पर अपने बयान में, जनसंख्या चुनौतियों को संबोधित करने में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि जटिल मुद्दों को समझने, उचित समाधान तैयार करने और सार्थक प्रगति करने के लिए व्यापक डेटा संग्रह में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी कहा कि कोई भी सटीक और समावेशी डेटा वह आधार है जिस पर कोई भी प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

भारत में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे :

भारत में जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे है –

जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना :

- भारत विश्व के क्षेत्रफल के केवल %2 भूभाग में ही सीमित है, लेकिन यहाँ की आबादी वैश्विक जनसंख्या का %16 है।
- भारत वर्तमान समय में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है और आने वाले समय में वह जनसंख्या के मामले में वह चीन से भी आगे निकल जाएगा।

भारत में जन्म और मृत्यु दर में अंतर उत्पन्न होना :

- भारत की जनसंख्या में पिछले कुछ दशकों में तेजी से वृद्धि हुई है।

- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में वर्तमान समय में भले ही गिरावट दर्ज की गई है।
- भारत में वर्तमान समय में कुल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर के करीब है।

शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि :

- शिक्षा का अभाव महिलाओं को गर्भ निरोधकों के उपयोग और अधिक बच्चों को जन्म देने से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी में बाधक है।
- जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- भारत में अखिल भारतीय स्तर पर कुल साक्षरता दर लगभग %77.7 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा अधिक है।
- महिलाओं की शिक्षा का स्तर उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालता है।

बेरोज़गारी :

- भारत में उच्च युवा बेरोज़गारी एक जनसांख्यिकीय लाभांश है, जिसे 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के रूप में भी जाना जाता है। भारत की युवा बेरोज़गारी जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा में बदल रही है।
- युवा क्षमता को उपयुक्त शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से लैस होने पर वे देश के आर्थिक विकास में भी प्रभावी योगदान कर सकते हैं लेकिन भारत में युवाओं को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से लैस किया जाता है तो उन्हें न केवल उपयुक्त रोज़गार मिलेगा बल्कि वे देश के आर्थिक विकास में भी प्रभावी योगदान दे सकते हैं।
- इस कदम से भारत न केवल अपनी इस उपलब्ध युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल सकता है , बल्कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी कर सकता है।
- इन मुद्दों पर समय-समय पर ध्यान देना और उन्हें समझना, समाधान ढूंढना आवश्यक है जिससे कि हमारी जनसंख्या के विकास में सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव हो सके।

समाधान / आगे की राह :

भारत में जनसंख्या वृद्धि के समस्याओं का समाधान और आगे की राह को तय करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश या समाधान निम्नलिखित हैं –

- **परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना :** जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए परिवार नियोजन एक प्रमुख उपाय है। सरकार, संगठन, और समाज को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझाने और इसे प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- **महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकारों की वकालत और जागरूकता को बढ़ावा देना :** महिलाओं को उनके यौन और प्रजनन अधिकारों की जागरूकता और पहुँच को बढ़ावा देना चाहिए।
- **भारत में गर्भनिरोधक के उपयोग को प्रोत्साहित करना :** भारत में गर्भनिरोधक के उपयोग को बढ़ावा देने से जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।
- **आर्थिक विकास के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतत् विकास को प्रोत्साहित करना :** भारत में व्याप्त गरीबी को कम करने, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वजानिक पहुँच को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इससे भारत में जनसंख्या वृद्धि के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
- इन दिशानिर्देशों के साथ, हम भारत में जनसंख्या वृद्धि के समस्याओं को समझने और उन्हें समाधान करने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. विश्व जनसंख्या दिवस वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के विषय पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
2. विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय/ थीम है – किसी को पीछे न छोड़ें, सभी की गिनती करें।
3. डॉ. के.सी. जकारिया के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
4. 1 जुलाई, 1989 को, दुनिया की जनसंख्या करीब 5 अरब दर्ज की गई थी।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है?

a. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 1, 2 और 4

C. केवल 2, 3 और 4

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. जनसांख्यिकीय लाभांश से आप समझते हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित विभिन्न समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसके समाधानात्मक उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। (UPSC – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नया वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वित्तीय समावेशन सूचकांक , विकास से संबंधित मुद्दे और रोज़गार , समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक का प्रकाशन , वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) , प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) , बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नया वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित ' खंड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) की घोषणा की है।
- वित्तीय समावेशन सूचकांक देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक माप होता है भारत में मार्च 2023 के 60.1 अंक से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) की ऐतिहासिक प्रगति :

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), देश के कमजोर समूहों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, समय पर ऋण और सामर्थ्य सुनिश्चित करने की प्रगति को मापने में मदद करता है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का उद्देश्य और निर्माण :

- वित्तीय समावेशन सूचकांक में 0 से 100 तक का मूल्य होता है, जिसमें 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
- वित्तीय समावेशन की गहराई को दर्शाने के लिए यह सूचकांक उप-सूचकांकों के योगदान पर आधारित होता है। यह सूचकांक भारत के वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत होता है जो देश के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- यह सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाओं और पेंशन को शामिल करने वाले 97 संकेतकों पर आधारित होता है।
- इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की गहराई और उपलब्धता को मापने में मदद करना है।
- यह सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के निर्मित किया गया है, जो पिछले कई वर्षों में वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है।

उप – सूचकांक और उसका मान / भार :

- **वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के आधार पर :** इसमें वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की आसानी को मापा जाता है जिसका मान / भार %35 होता है।
- **उपयोग के आधार पर :** इसके तहत वित्तीय सेवाओं के उपयोग की सीमा की गहराई को मापने के लिए किया जाता है , जिसका महत्व %45 होता है।
- **वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर :** इसमें वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है, जिसका महत्व %20 होता है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक का प्रकाशन :

- एफआई-सूचकांक (FI- INDEX) प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में आरबीआई का दृष्टिकोण :

- एफआई-इंडेक्स देश भर में आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण ऋण और सुरक्षा जाल तक देश के कमजोर समूहों या वर्गों तक पहुंच को सुगम बनाकर समावेशी विकास का समर्थन करता है।
- भारत में आधार और मोबाइल प्रसार के विस्तार होने से डिजिटल पहलों से संवर्धित यह रिपोर्ट वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भुगतान प्रणालियों की भूमिका को रेखांकित करती है।

वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) :

वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) का मुख्य

उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को सभी तक पहुंचाना है। इसके लिए कई पहल किए गए हैं। **जो निम्नलिखित है –**

- **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) :** यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को आम लोगों तक सबसे सस्ती और आसानी से पहुंच प्रदान करना है।
- **बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार :** प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है। इसमें बीमा और पेंशन योजनाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **शैक्षिक फोकस :** अनुकूलित मॉड्यूल और विस्तारित साक्षरता केंद्रों का लक्ष्य मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी कवरेज करना है। इससे वित्तीय साक्षरता में सुधार होगा और आम लोगों को वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।
- **वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में वृद्धि :** वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वित्तीय समावेशन के परिणामस्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है।
- इस तरह की तमाम योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

समाधान / आगे की राह :

- मार्च 4202 में वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार होकर 2 हो जाना, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों और प्रगति को उजागर करता है , जिसमें वित्तीय सेवाओं के बढ़ते उपयोग का महत्वपूर्ण योगदान है।
- एफआई-सूचकांक भारत भर में वित्तीय समावेशन की निगरानी और उसे बढ़ावा देने, रणनीतिक पहलों और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से आर्थिक उत्पादन को सुदृढ़ करने, गरीबी में कमी लाने और लैंगिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और वित्तीय पहुंच का विस्तार करने के लिए समन्वित प्रयासों के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है।
- ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना के विस्तार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर निरंतर जोर भारत में व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), भारत क्यूआर, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और रुपे कार्ड जैसे डिजिटल नवाचारों ने भारत के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन में क्रांति ला दी है।
- जन धन खातों, आधार और मोबाइल फोन (जेएएम ट्रिनिटी) के एकीकरण ने दूर से बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करके वित्तीय समावेशन को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है।
- बैंकिंग अवसंरचना के विस्तार और तमाम प्रगति के बावजूद, अभी भी बैंकिंग अवसंरचना के क्षेत्र में चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें बैंकिंग सेवाओं का असमान भौगोलिक वितरण और ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता शामिल है।
- समाज के सभी वर्गों में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

स्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वित्तीय समावेशन सूचकांक 0 से 100 तक के मूल्य का होता है, जिसमें 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
2. एफआई-सूचकांक (FI- INDEX) प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है।
3. यह सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाओं और पेंशन को शामिल करने वाले 97 संकेतकों पर आधारित होता है।
4. प्रधानमंत्री जन – धन योजना के तहत बीमा और पेंशन योजनाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं ।

D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि देश भर में व्यापक वित्तीय पहुँच प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को कैसे बढ़ाया जा सकता है ? (UPSC – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)